

(ग) विगत कुछ वर्षों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण खनिज खोजों में पूर्वी घाट बाक्सहाइट, मध्य प्रदेश के मलंजखंड में तांबा निक्षेप, राजस्थान में रामपुरा अगुचा में सीसा जस्ता निक्षेप आदि शामिल हैं। पूर्वी घाट बाक्सहाइट पर आधारित एल्यूमिनियम परियोजना के पूरा हो जाने से देश इस धातु में आत्म निर्भर हो जायेगा। मलंजखंड तांबा परियोजना तक द्वितीय चरण पूरा हो जाने से देश तांबा धातु के मामले में 50% तक आत्मनिर्भर हो जायेगा। उपर्युक्त सीसा-जस्ता निक्षेपों का दोहन होने पर चालू दशक के अन्त का सीसा और जस्ता के मामले में देश के लगभग 80 प्रतिशत तक आत्म निर्भर हो जाने की आशा है। उपर्युक्त अन्य खनिजों में से अनेक के प्रसंग में देश पहले ही आत्म निर्भर है।

बिहार के पिछड़ेपनको दूर करने लिए कदम

10637. श्री रामावतार शास्त्री : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार देश के अधिकांश राज्यों में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निष्कर्ष क्या है; और

(घ) उक्त निष्कर्षों के आधार पर बिहार का पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी. पाटिल) : (क) बिहार सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जैसा कि अनुमान लगाया गया है बिहार का वर्ष 1981-82 के लिए प्रतिव्यक्ति निवल देशीय उत्पादन 995 रु. है। यद्यपि राज्यों के लिए अनुमान ठीक तुलनीय नहीं है, फिर भी बिहार का प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पादन भारत में सबसे कम है। त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम नियमित आधार पर राज्य आय के अनुमान तैयार नहीं करते हैं इसलिए उन्हें तुलना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य के पिछड़ेपन के कारण, कृषि उपज की कम दरें, ग्रामीण जन संख्या के प्रतिव्यक्ति फार्म उत्पादन का कम मूल्य, फैक्ट्री क्षेत्रक में जोड़े गये प्रतिव्यक्ति मूल्य का कम स्तर और राज्य की कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का बड़ा प्रतिशत हो सकते हैं।

(घ) गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को आवंटित केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत का वितरण उन राज्यों में किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होती है, इनमें बिहार राज्य भी शामिल है। सिंचाई सुविधाओं के विकास, बीज, उर्वरक, ऋण आदि जैसे अन्य निवेशों के उपयोग के जरिये कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार आधार संरचना सुविधाओं में वृद्धि करने, नए उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहन देने और ऊर्जा की कमी को दूर

करने के लिए केप्टिव प्लाट डीजल जेन-रेशन सैट स्थापित करने के लिए राज सहायता देने संबंधी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय राज सहायता तथा रिसायती वित्त उपलब्ध हैं। ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जन जातीय उपतोजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना जैसे ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इस्पात संयंत्रों द्वारा ऊर्जा की खपत

10638. श्री रामकृष्ण मोरे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा की अर्थात् कोकिंग कोल, स्टीम कोल, पेट्रोलियम ईंधन, बिजली आदि, कुल खपत कितनी है;

(ख) इस अवधि में कितने बिक्री योग्य इस्पात बिक्री योग्य ढलवें लोहे का उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा की खपत आधुनिक विदेशी इस्पात संयंत्र से बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) पिछले 5 वर्षों में "सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (इस्को भी शामिल है) की ऊर्जा की कुल खपत इस प्रकार है :-

वर्ष	कोककर कोयला (शुल्क) हजार टन	केप्टिव पावर तथा पीसेस स्टील के लिए अकोककर कोयला (हजार टन)	खरीदी गई पावर (एम.यू.)	पेट्रोलियम पर आधारित ईंधन (हजार टन)	ऊर्जा का कुल निवेश 10 जी. ई.जी. ए. कैलरी
1979-80	10730	1809	1776	244	82.6
1980-81	10387	2018	1670	220	81.2
1981-82	11289	2131	2146	288	88.7
1982-83	11575	2393	2239	291	90.9
1983-84	11245	2439	2382	229	88.4